अगर जीवन में
कुछ पाना हो
तो अपने तरीके
बदलों, इरादे नहीं।
– अज्ञात

एक गहरी बहस का जन्म

विधानसभा अंततः जन प्रतिनिधियों की सभा है। राज्य की जनता अगर सीएए को नापसंद करती है तो उसकी इस राय को विधानसभा एक प्रस्ताव के रूप में देश के सामने क्यों नहीं ला सकती?

मोहन भट्ट।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विपक्ष शासित राज्यों के रवैये ने एक गहरी बहस को जन्म दिया है। वाम मोर्चे के नेतृत्व वाली केरल विधानसभा और कांग्रेस के वर्चस्व वाली पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। मामले को और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अपने नेतृत्व वाले बाकी राज्यों में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार 24 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा में लाने का निर्णय पहले ही कर चुकी है।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को ही दी गई है। लेकिन खुद कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस कानून को संवैध ाानिक करार दिया तो इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली सरकारों के लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि केंद्र के कानून के खिलाफ किसी विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना एक गलत परंपरा की शुरुआत है।

अमेरिका जैसे देशों में, जहां पूरी तरह संघीय व्यवस्था लागू है, भले ही ऐसा होता हो पर भारतीय व्यवस्था का स्वरूप अध ार्सिंघीय (क्वासी फेडरल) है। दूसरी तरफ ऐसा करने वाली विधानसभाओं के पक्ष में दलील यह दी जा रही है कि केंद्रीय कानून पर वे अपनी राय जाहिर कर सकती हैं, भले ही इसको अमल में लाने से मना करना उनके बूते से बाहर हो। विधानसभा अंततः जन प्रतिनिधियों की सभा है। राज्य की जनता अगर सीएए को नापसंद करती है तो उसकी इस राय को विधानसभा एक प्रस्ताव के रूप में देश के सामने क्यों नहीं ला सकती? यह भी कि राज्य विधानसभाओं के प्रस्ताव में यह कहीं नहीं कहा गया है कि राज्य सरकार इस कानून का पालन नहीं करेगी। बल्कि यह कहा गया है कि कानून में विसंगतियां हैं, इसलिए इसे वापस लेना बेहतर होगा। इस दलील को प्रस्तुत करने वालों के मुताबिक, यह संभवतरू पहला ऐसा कानून है जिसकी भाषा हमारे संविधान में प्रयुक्त भाषा से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हमारे संविधान की भाषा व्यापक मानवीय दायरे को संबोधित करने वाली है, किसी समुदाय का नाम लेकर उसे फायदा या नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात इसमें नहीं कही गई है।

विधानसभाओं द्वारा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को उचित ठहराने वालों का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून में संविधान की प्रकृति के विपरीत जाते हुए त्वरित नागरिकता के लिए कुछ खास समुदायों को चिह्नित किया गया है और एक धार्मिक समुदाय को सायास छोड़ दिया गया है। बहरहाल, देश के हर कानून की संवैधानिकता अंततरू सुप्रीम कोर्ट की चौखट से ही तय होती है, लिहाजा सभी पक्षों को उसकी व्याख्या का इंतजार करना चाहिए।

स्वस्थ चिंतन

डॉ. अर्चिका दीदी।

हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिस पर स्वस्थ चिंतन होना चाहिए था उस पर जो भी रुख अख्तियार किया गया ,उसके परिणाम अच्छे नहीं दिख रहे। इसलिए वर्तमान में इस विषय पर चिंतन की आवश्यकता है। विचारिए कि इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी सामान्य मनुष्यों ,महापुरुषों, सन्तों, विचारकों, वैज्ञानिकों का अवतरण तो इसी ऊर्जा से सम्भव हुआ है.. तो इस ऊर्जा के दमनात्मक तौर तरीकों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है ,जिसके परिणाम घातक रूप में हमारे समक्ष है । अतैव इस विषय की शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वह कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों को गैर जरूरी मानते हैं।

संपादकीय

जवाबी हमले की शक्ति

समुद्र से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की दुनिया में भारत ने एक अहम छलांग लगाई है। 19 जनवरी को भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली के–4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस तरह भारत ने सही मायने में त्रिआयामी परमाणु ताकत हासिल कर ली है। इसे हम आम शब्दों में न्यूक्लियर डिटरेंस यानी दुश्मन में परमाणु खौफ पैदा करने की ताकत भी कह सकते हैं। दुश्मन के परमाणु हमले का जवाब देने के लिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी दुश्मन पर जवाबी हमले की ताकत को इस परीक्षण के जरिये हासिल किया जा सका है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों ने सागरिका (के–15) नाम की सबमरीन लांच्ड बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) का परीक्षण करीब 12 साल पहले ही कर लिया था लेकिन इसकी मारक दूरी केवल 750 किलोमीटर थी।

पिछले एक दशक से विकसित की जा रही इस मिसाइल के परीक्षण पहले भी हो चुके हैं लेकिन अब भारतीय मिसाइल वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके ताजा परीक्षण सभी पैमानों पर खरे उतरे हैं और यह अरिहंत परमाणु पनडुब्बी पर तैनात करने लायक हो चुकी है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने जमीन से छोड़ी जाने वाली अग्नि श्रृंखला की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया है जिनमें अधिकतम 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि–5 मिसाइल भारतीय शस्त्र भंडार में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन जमीन की तुलना में समुद्री बैलिस्टिक मिसाइल का विकास तकनीकी रूप से काफी जटिल होता है। जाहिर है, भारतीय मिसाइल वैज्ञानिकों ने समुद्री मिसाइलों की दुनिया में अपनी क्षमता दिखा कर दुनिया की अन्य मिसाइल ताकतों को आगाह किया है कि भारत को कोई भी सैन्य ताकत अपनी परमाणु मिसाइलें दिखाकर ब्लैकमेल नहीं कर सकती।

इस मामले में आंतरिक उपद्रव से ग्रस्त केन्या और इजिप्ट जैसे देशों को भी हमसे ऊंची जगह मिली है। हालांकि, इस मामले में भी पिछले साल से हमारे हालात थोड़े सुधरे हैं।

जनाधार बचाने में जुटीं मायावती

रिचा जोशी।

बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों कांग्रेस पार्टी पर आग बबूला हो रही है। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा पिछले सप्ताह दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लिया था। मायावती का कहना था कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो विपक्षी दलों को एक साथ कर उनका नेतृत्व करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम करती रहती है। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक का बहिष्कार किया था।

मायावती ने बताया कि उन्होंने 10 साल तक केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार को बिना किसी शर्त के बाहर से समर्थन दिया था। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व अन्य जहां कहीं भी कांग्रेस को जरूरत थी उनकी पार्टी ने बिना शर्त समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब भी मौका मिलता है वह बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोडकर पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करती है। मायावती ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देकर उनकी

सरकार बनवाने में पूरी मदद की थी। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी पार्टी के सभी 6 विधायकों को दलबदल करवाकर कांग्रेस में शामिल करवा लिया जो बसपा के मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। इतना ही नहीं गहलोत के इशारे पर ही उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कोर्डिनेटर व राजस्थान प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम व राजस्थान प्रदेश संयोजक सीताराम मेघवाल का बसपा कार्यालय में मुंह काला कर जूतों की माला पहना गधों पर बिठा कर जूलुस निकाल कर बसपा की छवि खराब करने का प्रयास किया गया था। जिसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही हाथ था। गहलोत ने 2008 में भी उनकी पार्टी के सभी 6 विधायकों को तोड़ कर कांग्रेस में शामिल करवाया था। इस तरह बार–बार कांग्रेस द्वारा उनके विधायकों को तोडकर उनके जनाधार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

मायावती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी अपने निशाने पर ले रखा है। उन्होंने राजस्थान में कोटा के एक सरकारी अस्पताल में एक माह में 110 नवजात शिशुओं की मौत पर भी सवाल उठाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी छोटी–छोटी बातों पर धरना देने पर उतारू हो जाती है। जबकि राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वह जयपुर जाकर लौट आयी। उन्होने कोटा जाकर पीड़ित परिवारो से मिलना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने प्रियंका गांधी की ऐसी दोहरी नीति की भी आलोचना की। लोकसभा में बार–बार बसपा का नेता को बदलना मायावती में व्याप्त असुरक्षा की भावना को ही दर्शाता है। बसपा में काशीराम के जमाने के अधिकांश पुराने नेताओं को या तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर उन्हे अपनी अलग राह चुनने पर मजबूर किया गया था। जिस कारण आज बसपा में बहुत कम पुराने नेता रह गये हैं। बसपा में अब अन्य दलों से आने वाले नेताओं को तरहीज दी जाने लगी है।

सूडोकु नवताल- 5227

✱✲✲✲✲ सरल

3	9				1			
5	4			6	8		1	3
		1		7		9	5	
	8	9		5	3		4	7
6	1		4	9		2	3	
	3	4		1		8		
7	5		8	3			2	4
			6				7	9

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5226 का हल

9	6	2	3	4	1	7	5	8
1	4	8	9	7	5	6	2	3
5	7	3	2	6	8	1	4	9
3	2	1	6	9	4	8	7	5
4	8	7	5	1	2	9	3	6
6	9	5	8	3	7	4	1	2
8	3	4	7	2	6	5	9	1
2	1	6	4	5	9	3	8	7
7	5	9	1	8	3	2	6	4

अपना ब्लॉग: आंकड़ों का व्यवसाय

मुकुल श्रीवास्तव। सोशल मीडिया की आंधी में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी नई तकनीक कुछ लोगों की नौकरियां मारती है तो रोजगार के काफी सारे नए अवसर भी पैदा करती है। इस कसौटी पर सोशल मीडिया को अभी तक नहीं कसा गया है। साल 2018 में फेसबुक ने 55 अरब डॉलर और गूगल ने 116 अरब डॉलर विज्ञापन से कमाए। मजेदार बात यह कि फेसबुक कोई भी उत्पाद नहीं बनाता। डेटा आज की सबसे बड़ी पूंजी है। यह डेटा का ही कमाल है कि गूगल और फेसबुक जैसी अपेक्षाकृत नई कंपनियां दुनिया की बड़ी और लाभकारी कंपनियां बन गई हैं। डेटा ही वह ईंधन है जो अनगिनत संस्थानों को चलाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तमाम तरह के ऐप्स और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना किसी उत्पाद के भी सोशल मीडिया में रोजगार के कई सारे नए अवसर पैदा हुए होंगे।